Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

# विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट

## Research Team

**Manujam Pandey**
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design
**Suchit Kumar**

**Dr. Syama Prasad Mookerjee**
Research Foundation
9, Ashoka Road, New Delhi- 110001
Web www.spmrf.org, E-Mail: offce@spmrf.org
@spmrfoundation
Phone:011-69047014

# Index


1 - AI, Skills, Indian Knowledge Systems and Heritage – PM Modi's Commitment to "Vikas" and "Virasat" Page No. 8
**Dr. Anirban Ganguly**

2 - Budget To Make Viksit Bharat A Reality - Page No. 11
**Prof P. Kanagasabhapathi**

3 - **स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम :** Page No. 14
2025 के बजट में मोदी सरकार की ऐतिहासिक पहल
**डॉ विद्यासागर पाण्डेय**

4 - **Viksit Bharat –** Unlocking India with Budget 2025 Page No. 15
**JAGANNATHAN S.**

5 - **बजट 2025 :** भारत के विकास की नई दिशा Page No. 18
**प्रिया श्रीवास्तव**

6 - **भारत की अर्थव्यवस्था बदलने को मोदी सरकार प्रतिबद्ध** Page No. 20
**विकास पाठक**

7 - **बजट 2025 :**
100% एफडीआई से भारतीय बीमा उद्योग को कैसे मिलेगा लाभ Page No. 21
**मनोज गुप्ता**

8 - **Union Budget 2025-26:** Page No. 22
Transforming India's Education Landscape -
**Shivesh Pratap**

## SALIENT POINTS OF PM SHRI NARENDRA MODI ON BUDGET 2025

- Today is an important milestone in India's development journey! This is the budget of aspirations of 140 crore Indians, this is a budget that fulfils the dreams of every Indian. We have opened many sectors for the youth.
- The common citizen is going to drive the mission of developed India. This budget is a force multiplier. This budget will increase savings, increase investment, increase consumption and also increase growth rapidly.
- I congratulate Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and her entire team for this Janta Janardan ka Budget, People's Budget.
- Usually the focus of the budget is on how the government's treasury will be filled, but this budget is exactly the opposite of that. But this budget lays a very strong foundation on how the pockets of the citizens of the country will be filled, how the savings of the citizens of the country will increase and how the citizens of the country will become partners in development.
- Important steps have been taken in the direction of reform in this budget. The decision to promote the private sector in nuclear energy is very historic.
- This will ensure a major contribution of civil nuclear energy in the development of the country in the coming times. All areas of employment have been given priority in every way in the budget. But I would like to draw attention to two things, I would like to discuss those reforms, which are going to bring a big change in the coming times.
- One-Due to infrastructure status, the construction of big ships in India will be encouraged, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan will get momentum and we all know that ship building is the sector that provides the most employment.
- Similarly, there is a lot of potential for tourism in the country. For the first time, a lot of emphasis has been given to tourism by bringing the hotels that will be built at 50 important tourist destinations under the ambit of infrastructure.
- This will work to energize the hospitality sector, which is a very big area of employment, and tourism, which is the biggest area of employment, in a way, by creating employment opportunities all around.
- Today, the country is moving ahead with the mantra of development and heritage. In this budget, very important and concrete steps have been taken for this. Gyan Bharat Mission has been launched for the preservation of one crore manuscripts.

- Along with this, a National Digital Repository inspired by the Indian knowledge tradition will be created. This means that technology will be used to the fullest and the work of extracting nectar from our traditional knowledge will also be done.
- The announcements made for farmers in the budget will form the basis of a new revolution in the agriculture sector and the entire rural economy. Under the PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana, irrigation and infrastructure will be developed in 100 districts, and the Kisan Credit Card limit being increased to Rs 5 lakh will help them more.
- Now in this budget, income up to Rs 12 lakh has been exempted from tax. Tax has also been reduced for people of all income groups. Our middle class, people in jobs whose income is fixed, such middle class people are going to get a huge benefit from this. Similarly, people who have entered new professions, people who have got new jobs, this exemption from income tax will become a huge opportunity for them.
- There is a 360 degree focus on manufacturing in this budget, so that entrepreneurs, MSMEs, small entrepreneurs get strengthened and new jobs are created. Special support has been given to many sectors from National Manufacturing Mission to Cleantech, Leather, Footwear, Toy Industry. The goal is clear that Indian products can shine in the global market.
- This budget not only takes into account the current needs of the country, but also helps us prepare for the future. Deep Tech Fund for Startups, Geospatial Mission and Nuclear Energy Mission are such important steps. I once again congratulate all the countrymen for this historic People's Budget

"यह बजट हमारे सरकार के प्रयासों को जारी रखता है। विकास को तेज़ करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, घरेलू भावनाओं को ऊंचा उठाना, और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग की आवाज़ सुनी है, जो ईमानदार करदाताओं के रूप में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग कर रहे थे। इस प्रकार, यह बजट देश के सभी वर्गों के विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण**
वित्त मंत्री - भारत सरकार

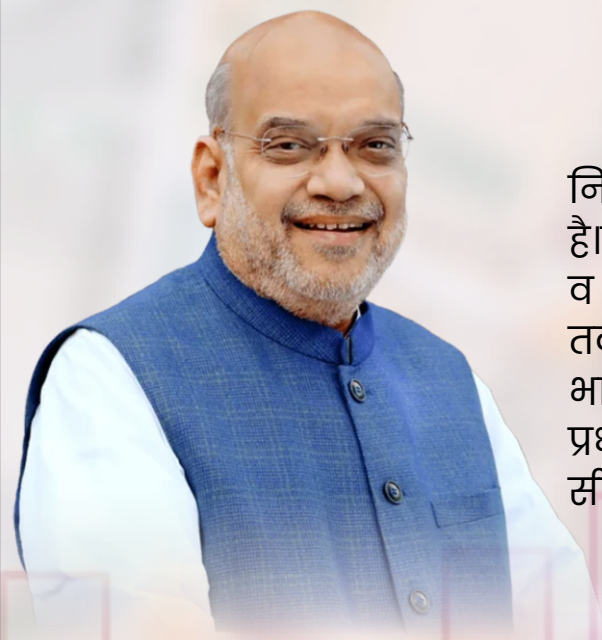

बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है।किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर Start Up, Innovation और Investment तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है।इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।

**श्री अमित शाह**
गृहमंत्री

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज प्रस्तुत किया गया आम बजट संतुलित, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला है। यह बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को तीव्र गति प्रदान करेगा। इसमें गरीब, किसान व मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। यह समावेशी व सर्वहितकारी बजट वंचितों का सम्मान सुनिश्चित करेगा और इसमें नारीशक्ति व मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा**
अध्यक्ष - भारतीय जनता पार्टी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री | रसायन और उर्वरक मंत्री - भारत सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास पर केंद्रित इस बजट में कृषि, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की घोषणा की है। इस योजना के तहत 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को आधुनिक कृषि तकनीकों और वित्तीय सहायता से सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार ने गारंटीकृत ऋण की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है, जिससे छोटे उद्यमों को अधिक वित्तीय सहयोग मिलेगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का नवाचार कोष स्थापित किया गया है, जिससे देश में नवाचार और तकनीकी क्रांति को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट 2025 मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कर राहत दी गई है, जिसमें 50,000 रुपये की छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इन सुधारों से जनता के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे उपभोग और बाजार में तेजी आएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत कम होगी। शिक्षा क्षेत्र में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को विज्ञान और तकनीक में नवाचार के अवसर मिलेंगे। 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे युवा पीढ़ी उन्नत तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेगी।

देश के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया गया है, जिससे भारतीय शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में, उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिससे 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी।

इसी क्रम में न्यायिक सुधारों के तहत, सरकार 100 से अधिक कानूनों के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। इससे व्यापार करने की प्रक्रिया आसान होगी और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है, जिससे करदाताओं को अधिक सहूलियत मिलेगी।

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट आर्थिक सुधार, सामाजिक उत्थान और बुनियादी ढांचे के विकास का संतुलित मिश्रण है। यह बजट किसानों, मध्यम वर्ग, स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योगों को समान रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। कर प्रणाली को सरल बनाकर, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर, और बुनियादी ढांचे में सुधार कर सरकार ने एक दूरगामी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

यह बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों का दस्तावेज़ है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रणनीतिक योजना ने इस बजट को एक मजबूत आर्थिक रोडमैप में तब्दील कर दिया है। यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि आने वाले दशकों में भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की नींव भी रखता है।

**डॉ अनिर्बान गांगुली**
चेयरमैन -
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

# AI, SKILLS, INDIAN KNOWLEDGE SYSTEMS AND HERITAGE

# PM Modi's Commitment to "VIKAS" & "VIRASAT"

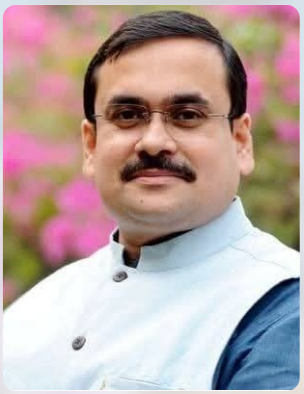

**Dr. Anirban Ganguly**

The ASER 2024 national findings on rural education have revealed a trend that is dynamic and positive. There has clearly been a post-Covid recovery and the education scenario, especially in rural India is on an upward trend.

In a massive countrywide rural household survey that covered over 6 lakh children in nearly eighteen thousand villages covering 605 rural districts, the ASER report's all India figures indicate that reading levels have improved for children in government schools in all elementary grades since 2022." It has also established that nationally, 'children's basic arithmetic levels also show substantial improvement in both government and private schools, reaching the highest level in over a decade."

Among the many significant findings in the report, is also an increasing and balanced growth of digital literacy. The digital divide in rural India, especially in the education sector is being addressed. Access to smartphones is "close to universal among the 14-16 age group and using smart phones for educational purposes was on the rise. This is a positive trend, keeping in mind that Prime Minister Modi had pledged to reduce and eventually eliminate the digital divide. Smart Classrooms also become effective with a decrease in the digital divide.

The Union Budget's proposal to extend broadband connectivity to all government secondary schools will ensure a further shrinking of the digital divide. This will bring about greater digital equity, especially in education, facilitating the emergence of new-age classrooms and of new pedagogic methods.

The proposed Bharatiya Bhasha Pustak Scheme aimed at providing "digital-format books in Indian languages for school and higher education" to enable students to better understand and absorb their subjects is another major digital step towards educational equity and democratisation. It is in line with the NEP's focus of enabling education in Indian languages and in one's own mother-tongue. This will also facilitate the spread of ideas and generate a more informed and multidimensional discussion of ideas and perspectives.

The Union Budget's declaration that it would further set up and nurture fifty thousand Atal Tinkering Labs in government schools in the next five years "to cultivate the spirit of curiosity and innovation, and foster a scientific temper", among young learners will give a further boost to this very refreshing and innovative flagship project. The move will unleash creative skills of young learners, train them to think and ideate critically and to innovate and invent. This is a major step towards realising the vision of India as a society and republic of innovations. The Atal Tinkering Lab scheme is proving to be popular with young learners and innovators in schools.

The decision to set up "National Centres of Excellence with global expertise and partnerships to equip youth with the skills required for "Make for India, Make for the World" manufacturing", will in due course, provide a wider arena for incubating ideas and training skills. Over the years, this will see India emerge as a global hub of talent and skill. With an increasing demand of skilled manpower globally, India can emerge as a major player in this field. It was a dimension which was repeatedly neglected in the past. There was an absence, in the past decades, of any serious attempt to upgrade the skill imparting mechanism and infrastructure. Skills taught in the past were often not in consonance with national and global demands. That lacunae has been addressed with a new direction, under Skill India mission, and shall leap to the next dimension with the proposal for setting up national centres for excellence across India.

Artificial Intelligence (AI) is fast emerging as the next arena and frontier of global engagement with its set of evolving challenges. These are bound to affect and influence a wide cross section of areas from education, to health, to national security, to media and politics. The decision to establish a Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education with a total outlay of Rs 500 crore is a futuristic and long-term move which will enable a more comprehensive dissemination of the AI dimension and empower and educate youth to engage with this new frontier with the approach of fulfilling the exigencies and goal of our national interest.

In keeping with his philosophy and approach of "Vikās" and "Virāsat" – of development and heritage, Prime Minister Modi lays emphasis on AI and on the preservation and dissemination of Indian knowledge systems. The proposal made in the

Union Budget for developing the Gyan Bharatam Mission which will work to survey, document and conserve "more than 1 crore manuscripts" that are in the possession and collections of academic institutions, museums, libraries and private collectors across the country. The proposed National Digital Repository of Indian Knowledge Systems for knowledge sharing is also a watershed step as far research on India is concerned. Both these decisions, that of undertaking a gigantic effort to preserve 1 crore manuscripts recognising the rich and unparalleled repository of knowledge produced by civilizational India and the proposed National Digital Repository of Indian Knowledge system are historic initiatives to correct a long neglect and apathy by past dispensations. Unprecedented in its scale and scope, these announce a new era in the field of research into India's civilizational past giving rise to the possibilities of new findings and perspectives.

The proposal to develop 50 top tourist destinations in the country in partnership with states is a possibilities-filled scope for states to upgrade infrastructure and connectivity among other things. The special focus to be given to historic places associated with Lord Buddha's life and times is in line with Prime Minister Modi's espousal of the vision of the Asian century with Lord Buddha's legacy as its defining core. In the last decade a wide ranging outreach and effort has been initiated by him in preserving the heritage and legacy associated with Lord Buddha's life and times. The declaration of Pali as a classical language and the re-establishment of the Nalanda University in a new dimension have been some of the most historic achievements of this unprecedented outreach in modern times. This special focus will cater to an increasing volume of international pilgrims who visit these sacred spots associated with Lord Buddha's life and will further cement India's civilizational linkages with countries that profess Buddhism and infuse them with fresh energy and scope.

The Union Budget 2025, with its emphasis and focus on AI, skills, Indian knowledge systems, research and preservation of our tangible sources of knowledge on civilizational India, and numerous heritage and sacred sites is a reflection of Prime Minister Modi's commitment actualising his vision of "Vikās" and "Virāsat."

---

**Author**
(The writer is a Member, National Executive Committee (NEC), BJP and Chairman of Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation. Views expressed are personal)

# BUDGET TO MAKE VIKSIT BHARAT A REALITY

**Prof P. Kanagasabapathi**

The budget for 2025-26 is a remarkable one in many ways. This is the first full budget of the Modi Government in its third term. The strong foundations laid by the first two Governments headed by Prime Minister Narendra Modi have made India the fifth largest economy in the World. There is all-round development in different sectors of the economy. The poor, farmers, youth and women are experiencing very positive changes in their lives.

As such this budget proposes to further build on the existing foundations to make the lives of Indians a better one. The proposals of the budget are in line with the vision of the Prime Minister to make India a Viksit Bharat by 2047.

For the first time, the salaried and middle- income categories are given a huge benefit by increasing the annual income tax limit to Rs.12 lakhs, a whopping increase of Rs 5 lakhs. This will enable them to have more money in their hands, which could lead to higher savings or increase in spending. The agricultural and the MSME sectors that remain the mainstay of our economy get new schemes and extra benefits in this budget.

A new scheme for agriculture, on the lines of Aspirational Districts Programme in operation for the overall of the development of the districts, has been announced to develop hundred districts with special thrust on agriculture, benefiting 1.7 crore farmers. Loans through Kisan Credit Cards are going to be increased from Rs 3 lakhs to Rs.5 lakhs, to enable the farmers to get more money. Besides, there is going to be a comprehensive programme for vegetables, fruits and Shri Anna. This is expected to greatly benefit the farmers who have severe problems such as storage, transport and marketing.

As for the MSME sector, the credit guarantee cover has been increased from Rs.5 crores to Rs. 10 crores. This has been one of their demands and would help the small and medium entrepreneurs in a big way. Micro enterprises that dominate the MSME sector are given the facility of getting Rs. 10 lakhs through credit cards. Once again the Start Ups have been given special attention to boost the growth in this segment further. Besides, there are measures for the labour -intensive segments to create more employment opportunities and a new scheme to make India the global hub for toys.

As for investments, 50000 Atal Innovation Laboratories are going to be set up to encourage and more youngsters. Most of the Government schools in the country still do not have broad- band connections, leading to children from the underprivileged

sections not getting the benefits available to those studying in private schools. Similarly, the Primary Health Centres run by the Governments catering to the ordinary people do not have the broad band connectivity. A new scheme has been announced to solve this critical problem.

Facilities to create 75000 additional seats in medical colleges and 6500 students in IITs are going to be set up. A Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education with an outlay of Rs 500 crores has been announced. This is necessary as Artificial Intelligence has started playing an important role in our lives and India has the potential to emerge stronger in this field. In the recent times, Gig workers are increasingly playing a larger role in the society. Government has announced a new scheme to give them recognition by registration through providing ID cards and enabling health care facilities to one crore workers.

Towards providing basic facilities to the ordinary sections of the society, the Jal Jeevan Mission will be extended till 20228 to achieve 100 percent success in rural areas. Cancer is becoming widely prevalent affecting different sections of the society. Hence to make the facilities easily available to all for consultation and treatment, cancer centres will be established in all the district hospitals across the country.

During the recent periods, the urban population has been continuously growing. Hence to the enable the cities and towns to cope up with the challenges and develop cities as ' Growth hubs' a new Urban Challenge Fund with Rs one lakh crore is going to be set up. For the financial year 2025-26, Rs 10000 crore would be allocated. Top 50 tourist destinations are going to be developed to increase the employment opportunities and encourage domestic tourism. Religious places connected with Lord Buddha are going to be connected to make people aware of the teachings of one of the greatest personalities of India.

Innovation continues to be the focus areas of Modi Government. Towards this a Fund of funds with Rs 20000 crores is going to be set up. 10000 Fellowships will be provided in IITs towards technical research. The Government has been continuously taking steps to increase our exports. To facilitate trade further, a digital platform for documentation to support domestic industries is going to be created. Global capability centres are planned in tier-2 cities.

National Pulses New Initiative to attain self-sufficiency in the cultivation of pulses, Special scheme to empower women through entrepreneurship by providing them low interest loans up to Rs 10 lakhs and skill development programmes, Agri Tech and Digital Economy Initiative to modernize farming, Remote Area Start Up Promotion Scheme to foster entrepreneurship in remote areas and Skilling centres are among the major steps announced in the budget for the overall and inclusive development of the economy.

Reforms continue to be one of the thrust areas of the budget. FDI in insurance sector has been increased to 100 per cent. Tax reliefs by giving full exemption to 36 life-saving drugs, besides support for domestic manufacturing have been announced. Support to states for infrastructure development with an outlay of Rs.1,50,000 crores by way of 50-year interest free loans would be provided. A high level committee would be set up towards regulatory reforms.

On the whole, this budget aims to accelerate further the growth momentum by creating opportunities for all to participate in the process so that the distance towards Viksit Bharat becomes closer.

---

**Author**
(The writer is Secretary & Trustee, Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, New Delhi. Views expressed are personal)

2025 के बजट में

मोदी सरकार की ऐतिहासिक पहल

# स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यह बजट "आत्मनिर्भर भारत" और "विकसित भारत 2047" के विज़न को आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल तकनीक, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, कैंसर उपचार, और सस्ती दवाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया गया है।**

डॉ विद्यासागर पाण्डेय

### मेडिकल शिक्षा में ऐतिहासिक विस्तार:

मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा को और सुलभ और व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त 10,000 मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा की है। अगले पांच वर्षों में कुल 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 1.1 लाख से अधिक मेडिकल सीटों में वृद्धि की है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूत कार्यबल तैयार हुआ है।

### कैंसर मरीजों के लिए राहत: 200 नए डे-केयर कैंसर सेंटर:

भारत में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को अधिक सुलभ बनाने के लिए हर ज़िले में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 2025 में 200 नए डे-केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, जहां मरीजों को कीमोथेरेपी और अन्य आवश्यक उपचार स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वास्थ्य में क्रांति:

स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इससे मेडिकल रिसर्च और हेल्थकेयर इनोवेशन को नया आयाम मिलेगा।वित्ता में सुधार लाने और अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) को अपनाने में तेजी लाने के लिए उठाया गया है।

### गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को हेल्थकेयर सुरक्षा:

मोदी सरकार ने गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अब इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, जिससे लाखों वर्कर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

### आयातित दवाओं पर कर छूट से सस्ती होगी चिकित्सा:

केंद्र सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, जिससे कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों की दवाएँ अब पहले से सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा, 37 अन्य आवश्यक दवाओं और 13 नए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम (PAPs) को भी कर छूट के दायरे में लाया गया है।

### गांवों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की पहल:

देश के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और गांवों में भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकेंगी।

### मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा: "Heal in India" अभियान:

भारत को वैश्विक स्तर पर मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने "Heal in India" अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से ₹20,000 करोड़ के अनुसंधान और विकास (R&D) प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे भारत की स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक प्रभावी और विश्वस्तरीय बनेंगी।

### निष्कर्ष: "सबका स्वास्थ्य, सबका विकास" की दिशा में बड़ा कदम:

मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025 स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। मेडिकल शिक्षा का विस्तार, कैंसर मरीजों के लिए राहत, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा, और सस्ती दवाओं जैसी पहलों से "सबका स्वास्थ्य, सबका विकास" के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है। यह बजट भारत को वैश्विक स्वास्थ्य हब बनाने और हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

**Author**

(लेखक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव हैं। प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं।)

VIKSIT BHARAT
UNLOCKING INDIA WITH BUDGET 2025

At 11 AM sharp amidst the wanton disturbance by the opposition, India's first full-time woman Finance Minister **Smt Nirmala Sitharaman** presented her 8th Union Budget. She commenced quoting Telugu poet and playwright **Shri Gurajada Appa Rao's** famous saying, 'A country is not just its soil; a country is its people.' This set the theme for Budget 2025 as **"Sabka Vikas"** -stimulating balanced growth of all sections, she laid out the broad Principles of **Viksit Bharat** to encompass the following:

- Zero-poverty.
- Hundred per cent good quality school education.
- Access to high-quality, affordable, and comprehensive healthcare.
- Hundred per cent skilled labour with meaningful employment.
- Seventy per cent women in economic activities; and
- Farmers making our country the 'food basket of the world'.

Moving on to the Budget Estimates 2025-26, she maintained a prudent fiscal path with deficit estimated to be 4.4 per cent of GDP. Fiscal prudence is something which the Modi government must be credited with, not once in the last 11 years has the government allowed clandestine slippage on the fiscal front. In fact, it was first under the **Vajpayee government in 2003** that India achieved fiscal prudence by enacting the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act in 2003, which set targets for reducing its fiscal deficit and debt-GDP ratio. Something which BJP led NDA governments can take credit for.

## Bharat's Growth Engines

With the plank of **Sabka Vikas** fuelling **Viksit Bharat**, Finance Minister outlined Four broad engines to bolster economic activity and fuel growth –

1 **Agriculture -** Spurring Agricultural Growth & Building Rural Prosperity

- **a.** National Mission on High Yielding Seeds
- **b.** Enhanced Credit through Kisan Credit Cards - Facilitate short term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers with enhanced loan of Rs 5 lakh
- **c.** Prime Minister **Dhan-Dhaanya Krishi Yojana :** Developing Agri Districts Programme - To cover 100 districts and likely to help 1.7 crore farmers.
- **d.** Mission for Cotton Productivity
- **e.** Makhana Board in Bihar - To be set up to improve production, processing, value addition, and marketing and organisation of FPOs

### Aatmanirbharta in Every Grain

A notable step by Modi Government is the aim to achieve Aatmanirbharta in Pulses, with a 6-year Mission with special focus on primary dal varieties such as Tur, Urad and Masoor – this is a highly commendable effort as this is the primary source of protein for majority of the citizens and better production means inflation will be under check.

### Game Changer in Last Mile Delivery to boost Rural Economy

India has the world's largest postal network, with over 164,972 post offices as of March 2024 across the country. Tapping this network, India Post will be an enabler to deliver assisted digital services to the last mile and deliver credit services to micro enterprises to boost rural economy.

## 2) MSMEs – Micro, Small & Medium Enterprises

Finance Minister's big push towards strengthening the small business ecosystem include a variety of measure such as enhancement of credit availability with guarantee cover for MSMEs and startups. Providing Credit Cards for Micro Enterprises with a Rs 5 lakh limit for enterprises registered on Udyam portal. Around 10 lakh such cards will be issued in the first year. Encouraging first-time entrepreneurs, including women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a new scheme, is being launched, to provide term loans up to Rs 2 crore during the next 5 years. Several sector specific measures have also been announced to catalyse individual sectors. All these measures will unleash the ease of credit across the value chain of MSMEs.

## 3) Investment – in People, Economy & Innovation

Investing in the right channels brings great dividends. Perhaps for the first time in Independent India's history Modi government has put people above everything else in this budget with huge outlay in increasing the medical seats – over 100,000 medical seats have been added since 2014 which is a 100% increase from the number that existed since independence, another 75,000 seats are being added in the next five years. 50,000 Atal Tinkering Labs to be set up in government schools in next 5 years. 5 National Centres of Excellence for skilling to be set up with global expertise and partnerships. Day Care Cancer Centres in all District Hospitals across the country – all these come to show the focus of government on people and making them the heart of this visionary budget 2025.

In a move to formalise the gig economy, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government will provide identity cards and registration for gig workers which is expected to benefit nearly 10 million (1 crore) gig workers, and will enhance social security and streamline benefits for the country's growing freelance and contractual workforce. Through registration on the e-Shram portal, gig workers can now access government welfare schemes. By obtaining an e-Shram card, they can access financial assistance and social security systems that are offered by the government.

## 4) Exports

A slew of measure to encourage exports from the country have also been undertaken by the government –

**Export Promotion Mission:** With sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.

**Bharat Trade Net:** A digital public infrastructure, 'BharatTradeNet' (BTN) for international trade will be set-up as a unified platform for trade documentation

and financing solutions. Support for integration with Global Supply Chains.

**National Framework for GCC:** As guidance to states for promoting Global Capability Centres in emerging tier 2 cities.

**Warehousing facility for air cargo:** To facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo including high value perishable horticulture produce.

## Leap of Faith

### Reforms as Fuel:

Financial Sector reforms and Development – which the Modi government has been tinkering with, some big bang reforms and some incremental but contiguous. From relooking at archaic laws to making income tax nil till Rs 12,00,000 of earning the finance minister has taken a leap of faith and put more money in the hands of the urban middle class. At the peak Income tax rate in the 1970's under congress rule, if one had an annual earning of Rs 12,00,000 the tax component would be Rs 11,29,007. With that kind of tax, it would only be encouraging non-compliance and incentivise generating black economy. Modi government has been continuously working to lower the income tax and this is a welcome move. Today the tax is nil at that slab. Some economists estimate the Rs 1 Lakh Crore additional disposable income in the hands of the middle class could generate up to Rs 5 Lakh Crore in additional consumption this year due to multiplier effect.

### Budget with a Soul

Budget 2025 was not just perception building exercise by any means, it was from the heart that Modi government delivered to the people of Bharat – an all-encompassing roadmap that will put India right at the top on path to becoming a Vishwa Guru. Budget 2025 has done well in stimulating the demand or consumption side of the economy given the supply side push in the previous Budgets. Maintaining this balance needs great understanding and Narendra Modi led NDA government has done the right thing in budget 2025. True to the words with which the finance minister started *"a country is its people,"* our beloved FM Nirmala Sitharaman has delivered a Budget with a soul that goes beyond rhetoric and vision statement.


**References**

https://www.india.gov.in/spotlight/union-budget-2025-2026

https://www.indiabudget.gov.in/

https://www.fortuneindia.com/long-reads/beyond-tax-relief-centre-through-budget-2025-has-given-a-fillip-to-infra-startups-and-msmes-says-jamshyd-godrej/120553

https://dea.gov.in/sites/default/files/FRBM%20Act%202003%20and%20FRBM%20Rules%202004.pdf


---


**Author**

**Jagannathan S.** is one of the **Directors of The Verandah Club**. He is an avid traveller, interested in trendspotting and a firm believer in the philosophy - Dharmo Rakshati Rakshitah. Expressed are personal

# बजट 2025
## भारत के विकास की नई दिशा

**बजट 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें जहां एक ओर निवेश को बढ़ावा देने की योजना है, वहीं दूसरी ओर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने और भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी गई है।**

——————प्रिया श्रीवास्तव

### आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन:

सरकार ने इस बजट में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत का सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात 83% है, जो अन्य देशों की तुलना में संतुलित स्थिति में है। कई विकसित और विकासशील देश इस समय भारी कर्ज के कारण मंदी और बढ़ती मुद्रास्फीति (महंगाई) की समस्या का सामना कर रहे हैं,लेकिन भारत की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 6 वर्षीय वित्तीय रोडमैप से संकेत मिलता है कि भारत आगे भी इस स्थिरता को बनाए रखेगा।

### विकास को गति देने के लिए बढ़ा सरकारी खर्च:

इस साल के बजट में कुल सरकारी खर्च में 7% की वृद्धि की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता मांग (खपत) को बढ़ावा देना है ताकि आम लोगों की क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) में इजाफा हो। इसके लिए आयकर दरों में व्यापक संशोधन, किसानों, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, मछुआरों और महिला उद्यमियों के लिए आसान ऋण योजनाएं और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।

### स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास:

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) को बढ़ावा देने के लिए इस बार ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹81,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% अधिक है। खासतौर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। अगर राज्य सरकारें आवश्यक सुधार लागू करती हैं तो उन्हें केंद्र से 50 वर्ष तक के लिए बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। यह कदम बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने और अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) को अपनाने में तेजी लाने के लिए उठाया गया है।

### परमाणु ऊर्जा में बड़ा निवेश:

बजट में परमाणु ऊर्जा को भी विशेष महत्व दिया गया है। सरकार ने 2033 तक पांच छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित करने की योजना बनाई है और इसके लिए ₹20,000 करोड़ का बजट तय किया है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 24x7 बिजली उत्पादन कर सकती है और इसका कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। साथ ही, नई तकनीकों के ज़रिए यूरेनियम के बजाय थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करने की योजना है, जो अधिक सुरक्षित और किफायती होंगे।

### भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को समान बढ़ावा:

भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग और सेवा) सर्विस दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की सफलता को देखते हुए सरकार ने दोनों क्षेत्रों को समान रूप से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सरकार ने कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके तहत अब भारत में ही उन मशीनों का उत्पादन किया जाएगा जो फार्मा, ऑटोमोबाइल और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में अंतिम उत्पाद निर्माण में उपयोग होती हैं।

## शिक्षा और कौशल विकास में निवेश

भारत की सबसे बड़ी ताकत यहां की युवा आबादी है। वर्तमान में देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और औसत आयु (मीडियन एज) मात्र 28 वर्ष है। इस जनसंख्या लाभ (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को भुनाने के लिए सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए ₹1.28 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है।

बजट में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, नए कौशल विकास केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग) स्थापित करने और उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।

## कृषि, निर्यात और उद्यमिता को बढ़ावा

सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।

## संतुलित और भविष्य उन्मुख बजट

बजट 2025 को संतुलित और दूरदर्शी कहा जा सकता है। यह एक ओर अल्पकालिक आर्थिक विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश के ज़रिए दीर्घकालिक विकास की नींव रखता है।

इस बजट के माध्यम से सरकार ने भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर और तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

**लेखक असम विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं**

# भारत की अर्थव्यवस्था बदलने को मोदी सरकार प्रतिबद्ध

**बजट 2025 में मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों से न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी लाभ होगा।**

**विकास पाठक**

### 100% FDI की स्वीकृति:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की स्वीकृति दी है, जो पहले 74% तक सीमित था। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा कंपनियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जिससे बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह कदम भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा।

### महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं:

बजट 2025 में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के तहत, 5 लाख महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन प्रदान किए जाएंगे। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे महिलाएं अपने व्यवसायों को बढ़ा सकेंगी और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगी।

### कृषि क्षेत्र में सुधार:

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

### पोषण 2.0 योजना:

बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त किया जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

### Ease of Doing Business में सुधार:

व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक की शुरुआत की गई है। यह कदम राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

### महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार:

महिला सम्मान बचत योजना की अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

### वित्तीय क्षेत्र में सुधार:

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना की गई है, जो नए नियमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी और वित्तीय क्षेत्र के विकास में योगदान करेगी। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देगा। इन पहलों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश की समृद्धि और विकास में योगदान करेंगे।

**लेखक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जनसंचार विभाग के प्राध्यापक हैं. प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं**

# 100% एफडीआई से भारतीय बीमा उद्योग को कैसे मिलेगा लाभ

2025 बजट

**वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य बीमा उद्योग को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है।**

मनोज गुप्ता

## बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

भारत में बीमा क्षेत्र ने पिछले दशकों में सीमित वृद्धि दर्ज की है। मैकिंज़ी एंड कंपनी की नवंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बीमा उद्योग की वृद्धि को "आधा भरा गिलास" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें उत्पाद नवाचार, वितरण दक्षता, और नवीनीकरण प्रबंधन में अंतराल हैं।

बीमा पैठ और घनत्व दो महत्वपूर्ण मानक हैं, जिनसे किसी देश के बीमा क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। बीमा पैठ को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, जबकि बीमा घनत्व को प्रति व्यक्ति प्रीमियम के रूप में। भारत में, बीमा पैठ 2001 में 2.7% से बढ़कर 2024 में 3.7% हो गई है, जबकि बीमा घनत्व $11.5 से बढ़कर $95 हो गया है। इसके विपरीत, 2024 में वैश्विक औसत बीमा पैठ 7% और बीमा घनत्व $889 है। यहां तक कि 2019 में, भारत की बीमा पैठ 3.76% थी, जो मलेशिया (4.72%), थाईलैंड (4.99%), और चीन (4.30%) से कम थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण 2020-2022 में कुछ वृद्धि देखी गई

## 100% एफडीआई से बीमा क्षेत्र पर प्रभाव

2000 में एफडीआई की शुरुआत के बाद से, भारत के बीमा क्षेत्र ने सितंबर 2024 तक ₹82,847 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। यह निवेश क्षेत्र की वृद्धि, संचालन में सुधार, और ग्राहक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में, 41 बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश है।

सरकार का लक्ष्य भारत के बीमा उद्योग की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है, जो अगले पांच वर्षों में 7.1% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है। एफडीआई की सीमा को 100% तक बढ़ाने से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी में सुधार होगा, और देशभर में बीमा पैठ में वृद्धि होगी।

## ग्राहकों को होने वाले लाभ

बढ़ते विदेशी निवेश से बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे बेहतर उत्पाद, उन्नत ग्राहक सेवा, और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संभव होगा। इससे बीमा पैठ में सुधार होगा और सुरक्षा अंतराल कम होगा। हालांकि, विदेशी भागीदारी बढ़ने के बावजूद, भारतीय नियामक प्राधिकरण (IRDAI) और सरकारी नीतियां यह सुनिश्चित करेंगी कि उद्योग पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करे।

## एफडीआई नियमों में संशोधन

विदेशी निवेशकों ने बीमा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी की आवश्यकता जताई है, विशेषकर विश्वसनीय घरेलू भागीदारों की खोज में। इसलिए, सरकार एफडीआई नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन नियुक्तियों और बोर्ड संरचना से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, ताकि विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।

## निष्कर्ष

बजट 2025 में 100% एफडीआई की स्वीकृति से भारतीय बीमा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। यह कदम बीमा क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन, और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

**लेखक भारतीय जीवन बीमा निगम - वाराणसी क्षेत्र के प्रबंधक हैं. प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं**

# UNION BUDGET 2025-26: TRANSFORMING INDIA'S EDUCATION LANDSCAPE

**Shivesh Pratap**

**Over the past decade, IIT student intake has doubled, from 65,000 in 2014 to 1.35 lakh today. This expansion reflects India's commitment to strengthening STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education.**

Education has long been recognized as the bedrock of a nation's progress. As Prime Minister Narendra Modi aptly stated, "Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, but it is also the architect of humanity's future." The Union Budget 2025-26 takes a giant leap in this direction by introducing transformative initiatives aimed at making India a global education hub. From expanding medical seats and enhancing skilling infrastructure to strengthening the IIT ecosystem, the budget outlines a forward-thinking approach to equipping India's youth with the necessary skills for the future.

## Key Announcements: A Roadmap for a Smarter, Inclusive India

### Bharatiya Bhasha Pustak Scheme

Language plays a crucial role in a student's ability to grasp concepts effectively. Recognizing this, the government has introduced the Bharatiya Bhasha Pustak Scheme, which aims to provide digitized books in Indian languages for both school and higher education. This initiative aligns with the vision of National Education Policy (NEP) 2020, which emphasizes education in the mother tongue for better learning outcomes. By making textbooks available in multiple regional languages, this scheme will promote inclusivity and ensure that students can understand complex subjects in their native language, reducing learning gaps and improving academic performance.

### National Centres of Excellence for Skilling

The government is focusing on bridging the skill gap by setting up five National Centres of Excellence for Skilling in partnership with global institutions. These centers will serve as hubs for skill development, covering curriculum design, trainer training, skills certification, and continuous improvement. Modernizing course content to match global industry standards will ensure that students are equipped with the latest skills. These centers will also prepare highly qualified trainers who can impart industry-relevant knowledge. Additionally, internationally recognized certifications will be provided to enhance employability, and regular assessments will keep training programs updated. By establishing these centers, India aims to equip youth with cutting-edge skills, boosting their job prospects in emerging sectors like AI, robotics, advanced manufacturing, and clean energy.

## Expansion of IITs

To meet the rising demand for quality technical education, the government is expanding infrastructure in five IITs that were established after 2014. This move will allow 6,500 additional students to enroll in top-tier engineering programs. IIT Patna will undergo major expansion, adding hostel and academic infrastructure. Over the past decade, IIT student intake has doubled, from 65,000 in 2014 to 1.35 lakh today. This expansion reflects India's commitment to strengthening STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education, ensuring that the country produces more highly skilled engineers and researchers to drive future innovation.

## Centre of Excellence in AI for Education

Artificial Intelligence (AI) is transforming education worldwide. To leverage this technology, the government is setting up a Centre of Excellence in AI for Education with a dedicated investment of Rs 500 crore. This center will develop AI-driven learning tools to enhance personalized education and support research in AI applications for education and pedagogy. It will also train teachers and students in AI-related fields, preparing them for AI-driven careers. Furthermore, the center will improve accessibility for students with disabilities through AI-powered assistive technologies. By integrating AI into education, India aims to revolutionize learning methodologies, making education more interactive, efficient, and customized to individual student needs.

## Expansion of Medical Education

The healthcare sector in India is witnessing rapid growth, and to support this, the government is making significant investments in medical education. In the last 10 years, UG and PG medical seats have increased by 130%, reaching 1.1 lakh seats. This year alone, 10,000 additional seats will be added across medical colleges and hospitals. Over the next five years, the government aims to add 75,000 more seats, further strengthening India's healthcare workforce. This expansion is critical for addressing India's growing healthcare needs, improving the doctor-to-patient ratio, and ensuring better access to medical services, especially in rural areas.

## India's Evolving Education System

India's education sector has undergone a remarkable transformation, catering to 24.8 crore students across 14.72 lakh schools, supported by a workforce of 98 lakh teachers. Government schools form the backbone of this system, constituting 69% of the total and enrolling 50% of students. Meanwhile, private schools, which account for 22.5% of institutions, serve 32.6% of students. This expansion reflects the dynamic shifts in India's education landscape and the continuous improvements in accessibility and enrollment.

## Enrollment Trends: Towards Universal Education

The National Education Policy (NEP) 2020 has set an ambitious goal of achieving a 100% Gross Enrollment Ratio (GER) by 2030, ensuring that every child has access to education. India has already made significant progress in this regard. The GER at the primary level is close to achieving universal coverage at 93%, reflecting strong foundational education access. However, challenges remain at higher levels, with GER at

the secondary level at 77.4% and higher secondary level at 56.2%. Despite these gaps, higher education enrollment has seen a remarkable surge, increasing from 3.42 crore students in 2014-15 to 4.33 crore in 2021-22, marking a 26.5% growth. Additionally, women's enrollment in higher education has risen by 32%, with notable participation in fields like Medical Science, Social Science, and Arts, indicating greater gender inclusivity in advanced education. This expansion in education access has led to greater social mobility, allowing students from marginalized communities to break the cycle of poverty. It has also contributed to economic empowerment, as a more educated population is better equipped to participate in high-value jobs and entrepreneurship.

### Reducing Dropout Rates

One of the critical challenges in achieving universal education is reducing dropout rates, and India has made steady progress in this area. At the secondary level, the dropout rate has significantly decreased from 21% in 2013-14 to 13% in 2021-22. Similarly, at the primary and upper primary levels, dropout rates have declined to 1.9% and 5.2%, respectively. This improvement is attributed to government initiatives, including scholarship programs, school infrastructure development, midday meals, and digital learning initiatives, which have encouraged more students to continue their education. The social impact of reducing dropout rates is profound, as it ensures that more young individuals gain essential knowledge and skills, reducing the likelihood of child labor, early marriages, and social exploitation. With more students staying in school, there is an increase in social awareness, leading to better civic engagement, reduced crime rates, and stronger community participation.

### Expansion of Higher Education Institutions

To accommodate the rising demand for higher education, India has undertaken massive expansion in the number of Higher Education Institutions (HEIs). The medical education sector has witnessed substantial growth, with the number of medical colleges increasing from 499 in FY19 to 780 in FY25, leading to a rise in MBBS seats from 70,012 in FY19 to 1,18,137 in FY25. In the field of technical and management education, IITs have grown from 16 in 2014 to 23 in 2023, while the number of IIMs has increased from 13 in 2014 to 20 in 2023. The overall university count has surged from 723 in 2014 to 1,213 in 2024, reflecting a 59.6% growth. The total number of HEIs has expanded from 51,534 in 2014-15 to 58,643 in 2022-23, demonstrating India's strong commitment to providing access to higher education for a growing student population. This expansion has bridged the rural-urban educational divide, bringing quality education closer to students in smaller towns and villages. It has also strengthened India's knowledge economy, producing a highly skilled workforce that can contribute to technological advancements, innovation, and global competitiveness.

### Strengthening Education Infrastructure

Infrastructure improvements have played a vital role in enhancing the quality of education across the country. Between 2019-20 and 2023-24, several advancements have been made in school facilities. The percentage of schools with separate girls' toilets increased from 96.9% to 97.2%, promoting better hygiene and retention of girl students. Access to libraries improved from 84.1% to 89%, ensuring that students have

more learning resources. Electricity availability in schools rose from 83.4% to 91.8%, reducing disruptions in teaching and learning. There was also a notable increase in schools with computers, rising from 38.5% to 57.2%, while internet availability jumped from 22.3% to 53.9%, enabling better digital education opportunities. These improvements have had a profound social impact, ensuring inclusive education for all, particularly for students from economically weaker sections. The availability of toilets and electricity has improved girls' attendance and retention rates, while digital infrastructure has connected rural students with global learning resources, reducing the urban-rural education gap.

## A Bold Vision for the Future

India's education sector has made tremendous progress in increasing enrollment, reducing dropout rates, expanding higher education institutions, and improving infrastructure. With continued efforts under the National Education Policy 2020, the country is moving closer to achieving universal education and ensuring that students receive quality learning opportunities at every level. These reforms are not only helping bridge educational gaps but also transforming society by creating an informed, skilled, and economically empowered population. Education is playing a crucial role in nation-building, fostering innovation, and strengthening India's global leadership in various fields. By prioritizing inclusive and accessible education, India is ensuring a more equitable and progressive future for all.

The government's continued focus on education, backed by initiatives aligned with NEP 2020, is shaping India into a global knowledge powerhouse. Programs like Samagra Shiksha Abhiyan, PM SHRI (Pradhan Mantri Schools for Rising India), and PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) are driving improvements in infrastructure, teacher training, and learning outcomes.

The Economic Survey underscores India's progress in making education more inclusive, accessible, and globally competitive. As the nation marches toward Viksit Bharat, the transformative steps taken in this budget will pave the way for a robust, knowledge-driven economy, ensuring that India's youth are equipped to lead the world in innovation, research, and development.

---

**Author**
(Shivesh Pratap is a seasoned technology management consultant, public policy analyst, author, and columnist. He holds a degree in Electronics Engineering and is an alumnus of IIM Calcutta, specializing in Supply Chain Management. Views expressed are personal)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

**Dr. Syama Prasad Mookerjee**
Research Foundation
9, Ashoka Road, New Delhi- 110001
Web www.spmrf.org, E-Mail: offce@spmrf.org
@spmrfoundation
Phone:011-69047014